an>

Title: Issure regarding crop procurement under Levy system.

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Hon. Deputy-Speaker, Sir, more than 60 per cent of our population depends on agriculture sector and farmers who produce paddy prefer to sell it to FCI for the Central Pool to get, at least, the MSP.

Now, I understand that Government is planning to totally lift procurement of paddy under Levy System. It will put farmer in a great disadvantageous position as he is not sure of getting even MSP from millers and traders.

This decision will impact greatly on States which produce and consume more. In this case, Andhra Pradesh, Telangana consume 80 per cent of what they produce unlike States like Chhattisgarh, Punjab, Uttar Pradesh where they produce but use very little. States like West Bengal, Assam, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Odisha also impact with the proposed decision to stop procurement through levy system.

Hence, I request the Government of India not to go ahead with the proposal and also remove the condition that only 25 per cent would be procured from farmers under Levy System for the Central Pool and request to restore the original 75 per cent procurement from farmers. Thank you.

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for calling me to raise an important issue. I have a very important issue today to raise. This issue has already been raised in the House because of the untimely बारिश और ओलावृष्टि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ुहुई ह उसके कांसेप्ट में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष वहां के गन्ना उत्पादकों को अभी तक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। मेरे बागपत संसदीय क्षेत्र में सैंकड़ों शादियां कैंसिल हुई हैं। इस बार रबी की फसल होने पर लोगों को आशा थी कि वे अपने बच्चों की शादियां कर सकेंगे, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल नष्ट हो गई है, लगता है कि इस बार भी उन्हें शादियां कैंसिल करनी पड़ेंगी। मेरी केन्द्र सरकार से तीन मांग हैं। पहली मांग यह है कि यू.पी. सरकार को कहकर गन्ना किसानों को बकाया राशि का भुगतान किया जाए। इसके अलावा केन्द्र सरकार का जो कम्पनसेशन रेट है 1500 रुपए प्रति हेक्टेयर का, उसे बढ़ाया जाए। मेरी तीसरी मांग है कि सरकारी और कोआपरेटिव बैंकों से जो लोन लिया गया है, उसके लिए बैंक रिकवरी एजेंट लगाते हैं। उसमें कम से कम एक साल का रिलीफ दिया जाए। किसानों का अपना पैसा है, उसमें जबर्दस्ती हैरासमेंट किया जाता है, उसे बंद किया जाना चाहिए।